

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 07 जुलाई, 2020

विषय:-सुन्दर मत्स्य जीवी सहकारिता समिति ग्राम गैड़ को सहकारिता के माध्यम से कलस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग किये जाने हेतु 0.379 है० भूमि सःशुल्क आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3188/उन्नचालीस-भूलेख (2016-2017), दिनांक 05 अप्रैल, 2020 तथा पत्र संख्या-2177/उन्नचालीस-भूलेख (2016-2017), दिनांक 11 फरवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम मादली के खसरा नं०-04 में रकबा 1.629 है० मध्ये 1.250 है० भूमि श्रेणी-9(2) अन्य प्रकार के वृक्ष व झाड़ियों का समूह तथा लम्बी घास इत्यादि हो, को ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु मत्स्य विभाग को प्रस्तावित है, तथा शेष 0.379 है० भूमि सुन्दर मत्स्य जीवी सहकारिता समिति ग्राम गैड़ को ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु लीज पर आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम मादली के खसरा नं०-04 में रकबा 1.629 है० मध्ये 1.250 है० भूमि श्रेणी-9(2) अन्य प्रकार के वृक्ष व झाड़ियों का समूह तथा लम्बी घास इत्यादि हो, को ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु मत्स्य विभाग हेतु प्रस्तावित है, तथा शेष 0.379 है० भूमि जिसका मूल्य राज्य में प्रचलित शानादेशानुसार धनराशि रू० 4,88,910/- (रूपये चार लाख अठ्ठासी हजार मात्र) निर्धारित किया गया है, को शासनादेश सं०-258/16(1)/73-राजस्व-1, दिनांक 09-05-1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-280-रा०-1, दिनांक-12-09-1997 तथा शासनादेश संख्या-1115/XVIII(II)/2016-18(184)/2015, दिनांक 15 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय सुन्दर मत्स्य जीवी सहकारिता समिति ग्राम गैड़ को ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सःशुल्क आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

- 2- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 3- प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्राण्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
- 4- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 5- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- 6- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 7- प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भूमि का श्रेणी परिवर्तन नियमानुसार अनुमन्य होने की स्थिति में इसकी श्रेणी परिवर्तन के पश्चात सीमा सुरक्षा बल को आवंटित की जायेगी।
- 8- चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि०-09.05.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- भू-उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
- 11- संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- 12— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या-474(1)/XVIII(II)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4— निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5— अध्यक्ष, सुन्दर मत्स्य जीवी सहकारिता समिति ग्राम गैड़, पो0 मनसूना, तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग।
- 6— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।